tive and stringent. Voluntary & Women's Organisations were also invited in this workshop to make their suggestions.

Job evaluation of doordarshan employees by National Productivity Council

278. SHRI AJIT P. K. JOGI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the National Productivity Council has been assigned with job evaluation and survey regarding Senior Engineering Assistants, Engineering Assistants, Technicians vis-a-vis Cameramen and Lighting Assistants of Doordarshan for the purpose of enhancement of their pay scales of doordarshan;

(b) if so, the reason for a comparative study or job evaluation between the employees of two altogether separate cadre| wings of Doordarshan having no similarity|comparison or parallel between them in any respect; and

(c) whether Government propose to continue to persue the job evaluation through National Productivity Council?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) to (c) The Engineering and Technical Staff Association of AIR & Doordarshan have pointed out that there is a disparity in the pay scales of certain categories of comparable posts in AIR and Doordarshan and demanded higher pay scales to the technical|engineering staff. In the context of discussions with the representatives of the employees it was decided that a professional body like the National Productivity Council should undertake a study on this and other related issues. The job evaluation would be continued either through the National Productivity Council or through a government agency.

Telecast and broadcast of Richas in the morning transmissions over AIR & TV

279. SHRI AJIT P. K. JOGI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to telecast and broadcast Richas (Mantras) from Vedas in devotional music programmes in the morning transmission; and

(b) if the reply to part (a) above be in the negative the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) and (b) At present, there is no such proposal. However, some of the All India Radio Stations include Vedic recitation in their programmes of devotional music. Songs of devotional nature in Semi-classical or classical style are also telecast in the morning transmission of Doordarshan.

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ आवंटित की गई धनराशियों का उपयोग

280. श्री अजीत जोगी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य-प्रदेश सरकार ने पिछले तीन वर्ष के दौरान केन्द्र-सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ प्रदान की गई सहायता की राशि का पूर्णतः उपयोग किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) वर्ष-वार प्रदान की गई सहायता राशि तथा खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ आवंटित की गई

धनराशि के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) से (घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कल्याण हेतु, पिछले 3 वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को प्रदान की गई सहायता राशि और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार किया गया व्यय इस प्रकार है :—

1. विशेष केन्द्रीय सहायता

वर्ष	भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि	मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार व्यय
1987–88	5735.34	5387.00
1988–89	6201.27	6051.00
1989–90	6930.89	8170.00

नोट:—वर्ष 1989–90 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा न केवल उस वर्ष के दौरान विमुक्त विशेष सहायता राशि का ही उपयोग किया गया अपितु पिछले वर्षों की व्यय न की गई राशि का भी उपयोग किया गया ।

2. केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्य केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में प्रदान की गई सहायता

वर्ष	भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि	व्यय
1987-88	986.75	986.75
1988-89	615.76	615.76
1989-90	1094.05	1094.05

मध्य प्रदेश सरकार ने बताया है कि उन्होंने राज्य में कार्यान्वयन तंत्र को, ठीक कर दिया है ताकि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग हो सके । मध्य प्रदेश सरकार की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान किए गए सहायता अनुदान का उपयोग कर लिया है। योजनाओं की एक सूची संलग्न है । (देखिए परिशिष्ट 157, अनुपत्र सं० 10)

बेरोजगारों को बेरोजगारी-भत्ते का दिया जाना

281. **श्री अजीत जोगी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने अथवा उन्हें रोजगार की गारंटी देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) केन्द्र सरकार का रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार-व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने अथवा रोजगार की गारन्टी देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

श्रम-न्यायालयों में लम्बित पड़े मामले

282. **श्री अजीत जोगी** :क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न श्रम न्यायालयों में लम्बित पड़े मामलों की राज्य वार संख्या कितनी है ;